RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 29 NOVEMBER TO 05 DECEMDER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 10 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

पैसे भेजने में लग सकता है 4 घंटे का टाइम ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड रोकने को सरकार की बड़ी तैयारी
Page 2

अब केवल 2.5 लाख में मिलेगी 2.2 करोड़ रुपये की दवा
Page 3

बिना भारत लौटे US वर्किंग वीजा रिन्यू होगा, इंटरव्यू भी जरूरी नहीं
Page 7

editoria!

बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात

वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के पहले सात महीने में देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के नियत में पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 27.7 प्रतिशत (3.4 अरब डॉलर) की उत्साहजनक वृद्धि हुई है. सरकारी और औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 15.48 अरब डॉलर मूल्य के इन उत्पादों का निर्यात हुआ. उल्लेखनीय है कि इस वृद्धि में 88 फीसदी हिस्सा (तीन अरब डॉलर) मोबाइल फोन के निर्यात का है. इस हिसाब की एक खास बात यह भी है कि पांच अरब डॉलर मूल्य के आइफोन का निर्यात हुआ है. मोबाइल फोन के निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि यह इंगित करती है कि आधुनिक तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तथा देश में निर्मित उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के भरोसे में बढ़ोतरी हो रही है. कुछ समय से केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार की आयात की निर्भरता घटाने तथा वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. अन्य योजनाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं. सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाने पर विचार कर रही है. इसमें वित्त मंत्रालय का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है ताकि वस्तुओं की आवाजाही सुचारू रूप से और समय पर हो सके. मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की मजबूत होती स्थिति इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं तकनीकों पर कई तरह के डिजिटल उपकरण बनाये जाते हैं. समय के साथ उनके उत्पादन में वृद्धि स्वाभाविक है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई कारणों से बदलाव हो रहे हैं, जिनमें कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियां, युद्ध एवं अन्य भू-राजनीतिक तनाव तथा डाटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं प्रमुख हैं. देश के शीर्ष के दस निर्यात क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में वृद्धि सबसे अधिक रही है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उचित ही कहा है कि देश एक ऐसे मुकाम पर है, जहां से तेजी से निर्यात बढ़ाया जा सकता है. सरकार हर क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश तथा साझा उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है. चीन और अन्य देशों में सक्रिय कंपनियां भारत को एक विशेष विकल्प के रूप में देख रही हैं. गुणवत्तापूर्ण साझा उत्पादन से देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और तकनीकी क्षमता भी बेहतर हो रही है. साथ ही, घरेलू बाजार को भी आपूर्ति की जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो रहा है. बीते नौ वर्षों में भारतीय मोबाइल उद्योग का 20 गुना विस्तार हुआ है, जो निश्चित ही एक उत्साहजनक उपलब्धि है.

खाड़ी देशों से ताबड़तोड़ तेल खरीद रहा भारत

रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचा इंपोर्ट, क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का ऑयल इंपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से अक्टूबर में 10 महीने के हाई पर पहुंच गया है। पिछले महीने से तुलना करें तो यह क्रमशः 63 फीसदी और 53 फीसदी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी तेल के लिए छूट कम होने के बाद रिफाइनर्स ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अधिक कच्चा तेल खरीदा है। अक्टूबर में भारतीय बाजार में रूस की हिस्सेदारी नौ महीने में सबसे कम हो गई है। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। यह आम तौर पर अपनी अधिकांश तेल जरूरतों के लिए मध्य पूर्व में उत्पादकों पर निर्भर करता है। बता दें कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मास्को से तेल खरीदना बंद करने के बाद दक्षिण एशियाई देश छूट पर बेचे जाने वाले रूसी समुद्री तेल के शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है। जानकारों के मुताबिक, भारत को रूस से तेल खरीदने में कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत

खाड़ी देशों के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहता है। इसकी वजह कॉरिडोर को बनाने में जी20 की बैठक में सहमति बनी हुई है।

अक्टूबर में इतना खरीदा तेल

आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने अक्टूबर में लगभग 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चे तेल का आयात किया है। यह पिछले महीने से 8.4% अधिक है। इसकी वजह त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ी हुई स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनर्स ने खरीदारी बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में उत्पादकों की हिस्सेदारी को अक्टूबर में 54% तक बढ़ाने में मदद मिली, जो सितंबर में 50% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने अक्टूबर में औसतन 1.56 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रूसी तेल का आयात किया, जो पिछले महीने से 1.2% अधिक है। इस इजाफे के बावजूद, भारत के अक्टूबर के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी सितंबर में 35% से घटकर 33% हो गई।

खूब खरीदा तेल

अप्रैल से अक्टूबर, इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों से लेकर मार्च तक रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता था, उसके बाद इराक और सऊदी अरब थे। आंकड़ों से पता चलता है कि रूसी तेल के अधिक खरीद से भारत के तेल आयात में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) की हिस्सेदारी अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सबसे अधिक हो गई।

क्या कम होंगे दाम

बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत (Petrol-Diesel Price) में एक साल से भी अधिक समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस साल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती करने का फैसला कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वह इस मामले में किसी तरह की घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं।

पूरी दुनिया में बजेगा भारत का डंका

साल 2026 तक चीन से आगे निकल जाएगी देश की इकॉनमी

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने मंगलवार को कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2026 तक बढ़कर सात प्रतिशत तक पहुंच जाएगी जबकि चीन के लिए इसके सुस्त पड़कर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 'चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र का वृद्धि इंजन चीन से हटकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि वर्ष 2024 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 4.6 प्रतिशत हो जाएगी जबकि 2025 में यह 4.8 प्रतिशत और 2026 में 4.6 प्रतिशत रहेगी। इसी के साथ हम भारत को वर्ष 2026 में 7.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि करते हुए देख रहे हैं।'

जताया ये अनुमान

इसके साथ ही एसएंडपी ने वर्ष 2026 में वियतनाम की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत, फिलीपींस की 6.4 प्रतिशत और इंडोनेशिया की वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान भी जताया है। रेटिंग एजेंसी ने एक दिन पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वर्ष 2025 के लिए यह दर बढ़कर 6.9 प्रतिशत और फिर 2026 में सात प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है।

महंगा होगा कर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया-प्रशांत देशों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरें ऊंची रखने की संभावना है जिससे कर्जदारों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। इसी के साथ पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने की आशंका भी है। इससे ऊर्जा लागत बढ़ सकती है जो मुद्रास्फीति बढ़ाने का काम करेगी।

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर भी 43 साल से एक कदम भी नहीं बढ़ सका यह देश

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में है। लेकिन फिर भी इस देश में महंगाई सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं कभी यह अमीर देशों की श्रेणी में आता था लेकिन 1980 के बाद से इसका विकास एक तरह से ठहर गया है। वेनेजुएला में साल 1980 में जीडीपी प्रति व्यक्ति 8,000 डॉलर थी और आज भी यह इसी स्तर पर है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 1980 में महज 2,000 डॉलर थी जो आज 56,000 डॉलर पहुंच चुकी है। यानी कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा पिछले 43 साल में 28 गुना बढ़ी जबकि इस दौरान वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति जीडीपी में एक पैसे का भी बदलाव नहीं हुआ है।

साउथ कोरिया ने जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर देकर खुद को हाई-इनकम वाले देश में बदल दिया, वहीं तेल पर वेनेजुएला की निर्भरता और राजनीतिक अस्थिरता ने वेनेजुएला को विकास की पटरी से उतार दिया। वेनेजुएला में रिटेल महंगाई दुनिया में सबसे अधिक है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। दुनिया के कुल क्रूड रिजर्व का 18.2इ इसी देश की कोख में दबा पड़ा है। यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको केवल 0.035 डॉलर यानी करीब 2.92 रुपये खर्च करने होंगे। यह पानी से भी सस्ता है। यह तो सिक्के का एक पहलू है।

जूठन खाने को मजबूर हैं लोग

दूसरा पहलू यह है कि इस देश में खाद्य पदार्थों की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालत यह है कि देश के लाखों लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। बेहतर जिंदगी की तलाश में लाखों लोग वेनेजुएला से पलायन कर गए हैं। देश में खाने-पीने की चीजें इतनी महंगी हैं कि अमीर लोगों के लिए भी दो जून की रोटी जुटाना भी भारी पड़ रहा है। कई गरीब लोग तो पेट भरने के लिए कचरे में पड़ी जूठन को खाने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह है कि प्राकृतिक आपदा से भरपूर वेनेजुएला की यह हालत कैसे हुई। देश में पिछले कई साल से खाने-पीने की चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बनी है।

जानकारों का कहना है कि इसके लिए देश की सोशलिस्ट नीतियां और अमेरिका के साथ टकराव जिम्मेदार हैं। ह्यूगो शावेज के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कर्ज के भुगतान के लिए बेतहाशा पैसे छापे। इससे करेंसी की कीमत काफी गिर गई। मादुरो ने 2019 में करेंसी कंट्रोल में छूट दी। रूढ़िवादी आर्थिक नीतियों के साथ-साथ सरकारी खर्चे में कमी और टैक्स में बढ़ोतरी से देश में करीब एक साल तक महंगाई सिंगल डिजिट में रही। लेकिन पिछले साल से अंत में वेनेजुएला में महंगाई तेजी से बढ़ी।

चैरिटी पर निर्भर

आज हालत यह हो गई है कि संपन्न लोग भी खाने पीने की चीजों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। देश के बाजार खाने-पीने की चीजों से भरे पड़े हैं लेकिन वे इतने महंगे हैं कि कम ही लोग उन्हें खरीदने में सक्षम हैं। लोग दिन में एक ही समय खाना खा रहे हैं या चैरिटी पर निर्भर हैं। देश की आधी से अधिक आबादी घोर गरीबी में जी रही है। एक सर्वे के मुताबिक 41 फीसदी से अधिक लोगों का कहना है कि वे रोजाना एक समय का खाना छोड़ रहे हैं। पिछले 43 साल में महंगाई तो चरम पर पहुंच गई लेकिन लोगों की इनकम एक ढेला भी नहीं बढ़ी है।

डॉलर के सामने गिरता रुपया, ऑल टाइम लो पर पहुंचा

आम लोगों की जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल यानी शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया छह पैसे की गिरावट के साथ अबतक के सबसे निचले स्तर 83.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। आयातकों की डॉलर मांग बढ़ने और एशियाई मुद्राओं में कमजोर रुख के बीच रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजार में नरमी का असर भी स्थानीय मुद्रा पर पड़ा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.33 पर खुला। कारोबार के दौरान रुपये में 83.33-83.40 प्रति डॉलर के दायरे में घट बढ़ हुई। कारोबार के अंत में रुपया, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.40 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे कम है। इसके पहले गुरुवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.34 पर बंद हुआ था।

आपकी जेब पर होगा ये असर

रुपये में गिरावट का सबसे बड़ा असर आयात पर पड़ता है। इससे आयात महंगा हो जाता है। वहीं निर्यात सस्ता हो जाता है। इसकी वजह ये है कि आयात की समान मात्रा का भुगतान करने में ज्यादा रुपये लगते हैं। निर्यात की समान मात्रा का भुगतान करने के लिए खरीदार को कम डॉलर लगते हैं। वहीं रुपये में गिरावट का ज्यादा असर उन आयातकों पर पड़ता है जो रुपये की कीमत प्रति डॉलर बढ़ जाने से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि रुपये का गिरना निर्यातकों के लिए सकारात्मक साबित होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपया मिलता है।

तेल की कीमत पर पड़ेगा असर

जानकारों के मुताबिक, भारत अपने कुल तेल का करीब 80 फीसदी तेल आयात करता है। रुपया जैसे-जैसे गिरेगा कच्चे तेल का आयात बिल भी बढ़ेगा। इसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं रुपये में गिरावट का सीधा असर उन छात्रों पर भी पड़ता है जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से भारतीय छात्रों के लिए विदेशों में शिक्षा ले पाना महंगा हो जाएगा। निर्यातकों के लिए रुपये का गिरना फायदे का सौदा है। क्यूंकि उन्हें विदेशी मुद्रा भुगतान को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने पर ज़्यादा राशि प्राप्त होगी।

पैसे भेजने में लग सकता है 4 घंटे का टाइम

ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड रोकने को सरकार की बड़ी तैयारी

सत्यम सिंह पंवार (गोल्डी)

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार दो व्यक्तियों के बीच पहली बार होने वाले किसी विशेष राशि से अधिक के लेनदेन के लिए न्यूनतम समयसीमा तय करने की योजना बना रही है। इसमें दो यूजर्स के बीच 2000 से अधिक के पहले लेनदेन के लिए संभावित 4 घंटे की विंडो भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। अधिकारियों का मानना है कि इससे साइबर फ्रॉड को कम किजा जा सकेगा। हालांकि, इससे डिजिटल पेमेंट में कुछ कमी भी आ सकती है।

पहले ट्रांजैक्शन में 4 घंटे की विंडो

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दो लोगों के बीच पहली बार होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाले न्यूनतम समय को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अनुसार, दो लोगों के बीच 2000 रुपये से अधिक के पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए समय सीमा 4 घंटे हो सकती है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGD) और यहां तक कि यूपीआई के माध्यम से होने वाले डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में आ सकते हैं।

बैठक में चर्चा की उम्मीद

एक सीनियर सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई, सरकार, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, गूगल और रेजरपे जैसी टेक कंपनियां सहित इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ बुधवार को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है।

बीते वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड

वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल पेमेंट में बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड नोटिस किये हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट 2022-23 में यह बात कही गई है। बीते वित्त वर्ष में बैंकों में कुल 13,530 फ्रॉड के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 30,252 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। हाल ही में यूको बैंक ने अपने खाताधारकों के खाते में आईएमपीएस के जरिए 820 करोड़ रुपये क्रेडिट कर दिये थे।

RBI ने इन 4 बैंकों पर कसा शिकंजा, लगाया करोड़ रुपयों का जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आरबीआई का बैंकों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आरबीआई ने एक घंटे में 4 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तगड़ा जुर्माना लगाया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटीबैंक एनए पर सबसे अधिक पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस वजह से लगाया जुर्माना

एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्ज को लेकर 'सेंट्रल रिपॉजिटरी' के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों के बारे में कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।

बैंक के निवेशक मंडल को हटाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को खराब संचालन मानकों के कारण अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को एक साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को एक साल के लिए मुंबई स्थित बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त की गई है। रिजर्व बैंक ने अभ्युदय सहकारी बैंक पर कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं लगाया है और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रखेगा।

2 साल बाद सरकारी कंपनी ने दिया सबसे बड़ा डिविडेंड, मिलेंगे 21 रुपये

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने 29 नवंबर 2023 को अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड (Dividend News) का बड़ा तोहफा दिया। आगे जानिए आपको हर शेयर पर कितना फायदा होगा और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। 21 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड (Dividend Stock) देने का ऐलान दिया है। यानी आपको हर शेयर पर 21 रुपए मिलेंगे. कंपनी ने डिविडेंड को लेकर एक्सचेंज में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2023 है।

इन्क्वायरी से लेकर टिकट बुकिंग तक के लिए GPT-4 तकनीक के साथ AI चैटबॉट

राम एस. पाल

इंदौर। बजट एयरलाइन इंडिगो ने जीपीटी-4 तकनीक द्वारा संचालित एक एआई चैटबॉट, 6ईस्काई (6Eskai) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 10 अलग-अलग भाषाओं में यात्रियों के प्रश्नों के जवाब देना और संपूर्ण नेटवर्क पर देश भर में टिकट बुकिंग के लिए अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म पेश करना है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इंडिगो की डिजिटल टीम ने इनहाउस डेवलप किया है।

मील का महत्वपूर्ण पत्थर

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के निकट सहयोग से इंडिगो की डिजिटल टीम द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस विकसित, एआई चैटबॉट एयरलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता के साथ, इंडिगो यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक एआई तकनीक का उपयोग करने वाली क्षेत्र की पहली कुछ एयरलाइनों में से एक बन गई है। प्रवक्ता ने कहा, 'सॉफ्ट लॉन्च के शुरुआती नतीजों से ग्राहक सेवा एजेंट के कार्यभार में उल्लेखनीय 75 प्रतिशत की कमी का संकेत मिलता है, जो बॉट की दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।'

आसानी से मिलेगा जवाब

प्रवक्ता ने कहा, 'एआई बॉट प्रभावशाली 1.7 ट्रिलियन पारामीटर्स को समेटे हुए है, जो इसे आम तौर पर पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का आसानी से उत्तर देने की अनुमति देता है। इंडिगो के डेटा वैज्ञानिकों की टीम ने जेनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफार्मर (जीपीटी) पर भारी अनुसंधान किया है और व्यापक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उपयोग करके बॉट को प्रोग्राम किया है। यह मानव व्यवहार की नकल करता है, भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है और यहां तक कि बातचीत में हास्य शामिल कर अपने यात्रियों के लिए अधिक आकर्षक और मनोरंजक अनुभव सुनिश्चित करता है।''

क्या हो सकेगा इससे

प्रवक्ता ने आगे कहा कि 6ईस्काई कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, जिसमें टिकट बुक करना, प्रमोशनल छूट लागू करना, ऐडऑन बुक करना, वेब चेक-इन करना, सीट चयन में मदद करना, यात्रा की योजना बनाना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और ग्राहकों को एक एजेंट के साथ जोड़ना शामिल है। इसके अलावा, बॉट न केवल लिखित या टाइप की गई भाषा को समझने में सक्षम है, बल्कि स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल का उपयोग करके मौखिक निर्देशों को भी समझने में सक्षम है।

IOC और GAIL समेत कई सरकारी कंपनियों पर फिर लगा जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल और गेल (इंडिया) लिमिटेड समेत तेल एवं गैस सेक्टर की कई सरकारी कंपनियों पर लगातार दूसरी तिमाही जुर्माना लगा है। इन कंपनियों के बोर्ड में नियमों के मुताबिक स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी संख्या नहीं है। यही कारण है कि उन पर जुर्माना लगाया गया है। बीएसई और एनएसई ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर 5.42-5.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी जानकारी में इस जुर्माने के बारे में बताया है। हालांकि इन कंपनियों ने साथ ही दावा किया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार के अधीन है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इन सभी कंपनियों पर एक बराबर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ओएनजीसी पर पिछली तिमाही में 3.36 लाख रुपये, आईओसी पर 5.36 लाख रुपये और गेल पर 2.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लिस्टिंग नियमों के मुताबिक कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। साथ ही बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर भी होनी चाहिए।

अब केवल 2.5 लाख में मिलेगी 2.2 करोड़ रुपये की दवा

नई दिल्ली। एजेंसी

दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई चार दवाओं की मार्केटिंग को मंजूरी दे दी है। ये दवाएं आयातित दवाओं की तुलना में काफी सस्ती हैं। उदाहरण के लिए टायरोसिनेमिया टाइप वन बीमारी के इलाज में काम आने वाली दवा Nitisinone कैप्सूल की सालाना कीमत 2.2 करोड़ रुपये है। इसे विदेशों से आयात किया जाता है। लेकिन देश में बनी दवा की कीमत 2.5 लाख रुपये होगी। यह एक दुर्लभ बीमारी है। एक लाख की आबादी में इसका एक मरीज पाया जाता है।

इसी तरह आयात की जाने वाली Eliglustat कैप्सूल की सालाना खुराक की कीमत 1.8 से 3.6 करोड़ रुपये बैठती है। लेकिन देश में बनी इस दवा की कीमत तीन से छह लाख रुपये होगी। यह दवा Gaucher's बीमारी के इलाज में काम आती है। अधिकारियों के मुताबिक Wilson's नाम की बीमारी के इलाज में काम आने वाली Trientine कैप्सूल के आयात पर सालाना 2.2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। लेकिन देश में बनी इसकी दवा पर सालाना मात्र 2.2 लाख रुपये खर्च होंगे।

सिकल सेल एनीमिया की दवा

Gravel-Lennox Gastaut Syndrome के इलाज में काम आने वाली दवा Cannabidiol के आयात पर सालाना सात से 34 लाख रुपये तक खर्च आता है। लेकिन देश में बनी इसकी दवा एक लाख से पांच लाख रुपये तक में उपलब्ध होगी। अधिकारियों का कहना है कि सिकल सेल एनीमिया के इलाज में काम आने वाली दवा Hydroxyurea Syrup की कमर्शियल सप्लाई मार्च 2024 में शुरू होने की संभावना है और इसकी कीमत 405 रुपये प्रति शीशी हो सकती है। अभी इसकी 100 मिली की शीशी की कीमत 840 डॉलर यानी 70,000 रुपये है। ये सभी दवाएं अब तक भारत में नहीं बनती थीं।

एक अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद घरेलू कंपनियों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली जेनरिक दवाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी और फार्मा इंडस्ट्री, सीडीएससीओ, दवा विभाग और दूसरे कई स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा हुई है। सिकल सेल के साथ-साथ 13 दुर्लभ बीमारियों को प्रायोराइज किया गया है। इसके बाद दवा बनाने वाली कंपनियों और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बीच बातचीत हुई। अब इन दवाओं को मंजूरी दे दी गई है।

RBI मॉनिटरी पॉलिसी दिसंबर में रेपो रेट पर यह फैसला ले सकता है आरबीआई

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रख सकता है। अगले महीने होने वाली बैठक में अपना रुख नहीं बदलेगी। अगले महीने 6 से 8 दिसंबर के बीच आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी समिति की बैठक होगी। इस पॉलिसी में रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। यानी होम और कार लोन समेत सभी तरह के लोन की बढ़ी ईएमआई से राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है। आपको बता दें कि महंगाई औसतन पूरे साल के लिए 5.5 फीसदी रहेगी। अक्टूबर में मुद्रास्फीति दर घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई है, लेकिन फिर भी केंद्रीय बैंक रेपो दर में संशोधन नहीं करेगा। वह महंगाई को लेकर चौकन्ना है।

इसलिए बदलाव की उम्मीद नहीं

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने आईएएनएस को बताया कि हम आगामी नीति में रेपो रेट और रुख दोनों पर यथास्थिति की उम्मीद करते हैं। विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। अनाज और सब्जी दोनों के दाम बढ़ रहे हैं। पूरे साल के लिए मुद्रास्फीति औसतन 5.5 प्रतिशत होगी। इसलिए रेपो दर में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके मुताबिक, राहत देने वाली बात ये है कि कोर इन्फ्लेशन कम रहेगी।

आरबीआई ने उठाया है यह कदम

इस साल नवंबर के लिए आरबीआई के 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' मासिक बुलेटिन का हवाला देते हुए श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा कि इससे कम दर व्यवस्था की वापसी की उम्मीद जगी है। रेवनकर ने कहा, लेकिन सिस्टम में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपभोक्ता ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्य और एनबीएफसी एक्सपोजर पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 125 प्रतिशत तक कर दिया गया है। आरबीआई मुद्रास्फीति पर अपनी निगरानी जारी रखना चाहता है। उन्होंने कहा, एमपीसी रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखेगी क्योंकि इसका लक्ष्य प्रणाली में तरलता को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत मध्यम अवधि के लक्ष्य के आसपास स्थिर करना है। रेवनकर ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक दरों में कोई कटौती नहीं होगी।'

भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार

एक सप्ताह में हुई 5 बिलियन डॉलर की बढ़त

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले एक सप्ताह में 5 बिलियन डॉलर (लगभग 41,657 करोड़ रुपए) से अधिक बढ़ कर 595.4 बिलियन डॉलर (लगभग 49,60,560 करोड़ रुपए) हो गया है। यह बीते लगभग 3 महीने में सबसे ऊँचा स्तर है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। बीते चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में यह सबसे बड़ी बढ़त है। इससे पहले के सप्ताह में यह लगभग 462 मिलियन डॉलर घट गया था।

यह जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी है। भारत से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार केवल चीन, जापान और स्विटज़रलैंड के पास हैं। चीन के पास 3.1 ट्रिलियन डॉलर जबकि जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार हैं। स्विटज़रलैंड के पास 809 बिलियन डॉलर से अधिक के भंडार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत स्थिति में होना उसकी बढ़ती अर्थव्यस्था को दिखाते हैं। जिन देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती है, वह अधिकांश समय विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे होते हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका एक उदाहरण है।

क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार?

विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश या उसके केन्द्रीय बैंक के पास संचित ऐसी धनराशि होती है, जिसका उपयोग कर वह विदेशों में अपनी खरीददारी का भुगतान कर सके। किसी भी राष्ट्र का विदेशी मुद्रा भंडार उसकी आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

इसमें कमी आने पर विदेशों को किए जाने वाले भुगतान में समस्या आती है, जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। इसका हालिया उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। भारत के साथ ऐसी स्थिति वर्ष 1991 में हुई थी, जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के 4 कंपोनेंट – विदेशी मुद्रा, सोना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और घ्श्इ में रिज़र्व पोजीशन होते हैं। इनमें सबसे मुख्य दूसरे देशों की मुद्रा का रिज़र्व है। इसके अंतर्गत भारत डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी करेंसी संचित करता है। इसमें भी सबसे प्रमुख अमेरिकी डॉलर है। भारत के पास वर्तमान में 526 बिलियन डॉलर मुद्रा भंडार है, जबकि 46 बिलियन डॉलर का सोना है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अंतर्गत भारत के पास 18 बिलियन डॉलर हैं। भारत जब चाहे इन्हें उपयोग में ला सकता है। रिजर्व पोजीशन, घ्श्इ के पास जमा देश का पैसा होता है। अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 645 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। इसके पश्चात फरवरी 2022 में यूक्रेन-रूस युद्ध चालू होने के कारण डॉलर मजबूत हुआ, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। कच्चे तेल के महँगे होने का असर भी इस पर पड़ा।इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग व्यापार के अतिरिक्त, देश की मुद्रा को स्थिर करने में भी किया जाता है। यदि रुपया अधिक कमजोर हो रहा है तो रिजर्व बैंक अपने रिज़र्व से डॉलर बाजार में बेच कर उसकी कीमत को स्थिर रखती है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम विदेशों से व्यापार होता है। भारत, कच्चे तेल का आयातक होने के कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देता है। जो देश आयात पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या बनी रहती हैं।

मॉडर्न लैबोरेटरीज इंदौर के डॉ. अनिल खरया दिल्ली में सम्मानित

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय फार्मा उद्योग ने अपने संघर्ष का सामर्थ्य दिखाया है जब दिल्ली में आयोजित ओ.पी.पी.आई वार्षिक समिट में एम.एस.एम.ई कैटेगरी में इंदौर की फ़ार्मा मैनुफ़ैक्चरिंग कंपनी, मॉडर्न लैबोरेटरीज को 'एप्रीशियेशन एवार्ड' से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को कंपनी के सी. एम.डी डॉ. अनिल खरया को प्राप्त हुआ। मॉडर्न लैबोरेटरीज ने अपने उच्च गुणवत्ता और नवाचारी उत्पादों के लिए इस सम्मान को प्राप्त किया है। इस कंपनी का उद्देश्य अपने ग्राहकों को एकमात्र उत्कृष्ट और सुरक्षित उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। उनके इनोवेटिव उत्पादों और उनके सुरक्षित और प्रभावी तकनीकों की वजह से कंपनी को इस सम्मान का हकदार बनाया गया है।

डॉ. अनिल खरया ने इस सम्मान को प्राप्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और यह उनके पूरे टीम के मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। वह कहते हैं कि उनकी कंपनी ने हमेशा से नवाचार को प्रोत्साहित किया है और इस सम्मान से उन्हें और उनकी टीम को आत्म-विश्वास मिला है कि वे अपने काम में सही रास्ते पर हैं। फार्मा उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और यह सम्मान उसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह सम्मान दिखाता है कि भारतीय फार्मा उद्योग में नवाचार और गुणवत्ता को सराहनीय रूप में माना जा रहा है और उसे सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे दूसरे फार्मा कंपनियों को प्रेरित किया जाएगा कि वे भी नयी तकनीकों का उपयोग करके और नयी उत्पादों का निर्माण करके बेहतर उत्पादों को प्रदान करे। इससे यह साबित होता है कि भारतीय फार्मा उद्योग अभिवृद्धि की राह पर है और उसका भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है। समाप्त करते हुए यह कह सकते हैं कि इस सम्मान ने मॉडर्न लैबोरेटरीज के उद्देश्य को सम्मानित किया है और उसे और भी महत्वपूर्ण बनाया है। इसके साथ ही भारतीय फार्मा उद्योग के प्रति भरोसा और विश्वास भी मजबूत हुआ है।

यूरोप में हो गई डीजल की किल्लत, भारत को होने लगा तगड़ा मुनाफा

डीजल निर्यात 3 लाख बैरल प्रतिदिन के पहुंचा पार

नई दिल्ली। एजेंसी

यूरोप को इस समय डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक साल पहले रूस से कच्चा तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप को डीजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब यूरोप ने घरेलू जरूरतों को पूरा

करने के लिए भारत का रुख किया है। भारत से यूरोप को किए जाने वाले डीजल का निर्यात बढ़ गया है। यह अब 3 लाख बैरल प्रति दिन के करीब पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना है।

डीजल का निर्यात बढ़ने से भारत को फायदा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई स्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड ने पिछले साल रूस से हुए कुल कच्चा तेल आयात का लगभग 60 फीसदी हिस्सा खरीदा था। यह कंपनी यूरोप में भी डीजल भेज रही है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इंडियन डीजल का यूरोप में टॉप सप्लायर है। रिलायंस भी अपनी जरूरतों का एक तिहाई हिस्सा रूस से ही खरीदता है।

रूस का डीजल था लाइफ लाइन

बता दें कि यूरोप के लिए रूस का डीजल लाइफलाइन था। रूस से ही यूरोप में सबसे ज्यादा डीजल जाता था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का इसपर काफी असर पड़ा है। वहीं प्रतिबंधों की वजह से भी यूरोप में उद्योग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूरोप ने भारत के साथ कई और जगहों से डीजल को मंगाने के विकल्प तलाशे हैं। अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब से भी तेल यूरोप जा रहा है।

यूरोप में ऐसे पहुंच रहा रूसी डीजल

बता दें कि रूसी क्रूड ऑयल के बड़े खरीदारों में भारत भी शामिल है। भारत रूस के साथ अन्य देशों से भी कच्चा तेल खरीदता है। इसके बाद देश की रिफायनरीज इसे डीजल में तब्दील कर देती हैं। इससे देश को डीजल निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह से भारत के रास्ते रूसी डीजल यूरोप के देशों में पहुंच रहा है।

सैटेलाइट इंटरनेट पर आमने-सामने आएंगे जियो और एयरटेल

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में अब सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच प्रतिस्पर्धा एक नए लेवल पर पहुंच रही है। दरअसल अब आने वाले समय में देश में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। भारती एयरटेल की वन वेब को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए इन स्पेस से अप्रूवल भी मिल चुका है। एयरटेल को भारत में इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस को शुरू करने के लिए इन स्पेस से सभी जरूरी अप्रूवल मिले हैं। भारतीय एयरटेल की वन वेब की ओर से इस बारे में बीते दिनों जानकारी शेयर की गई थी। आपको बता दें कि IN-SPACe एक सरकारी एजेंसी है। यह अंतरिक्ष गतिविधियों को रेगुलेट करने और देश में अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन के लिए परमिशन देने के लिए जिम्मेदार है।

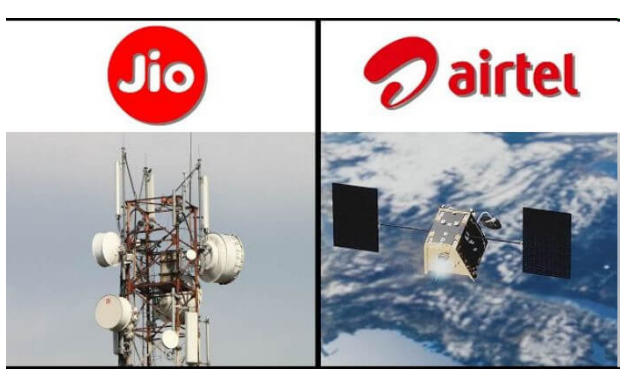

भारतीय एयरटेल बनी पहली कंपनी

बता दें कि ये अप्रूवल हासिल करके भारती एयरटेल के स्वामित्व वाला वन वेब देश का पहला संगठन बन गया है। एयरटेल ग्रामीण और अनकनेक्टेड एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती है। कंपनी की तैयारी लोगों को हाईस्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट देने की है। इधर जियो के मालिक मुकेश अंबानी की अब सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में सीधी टक्कर सुनील मित्तल की एयरटेल से होने जा रही है।

शुरुआती दौर में है बाजार

हालांकि भारत में अभी सैटकॉम बाजार शुरुआती चरण में है, लेकिन विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (ण्ॅ) से बढ़ते हुए 2025 तक 13 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

टेलीकॉम दिग्गज आमने-सामने

IN-SPACe से अप्रूवल के साथ, यूटेलसैट वनवेब ने सभी जरूरी अनुमतियां सुरक्षित कर ली हैं। अब वाणिज्यिक कनेक्टिविटी सेवाएं शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) से स्पेक्ट्रम आवंटन की जरूरत है। कई लोग इसे भारती एयरटेल द्वारा रिलायंस जियो पर बढ़त हासिल करने के रूप में देखेंगे। दरअसल, कुछ महीने पहले भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि अगले पांच-छह वर्षों में वनवेब की सैटकॉम सेवाओं के लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धी एलोन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक और अमेज़ॅन हैं। यह स्पष्ट रूप से रिलायंस जियो पर कटाक्ष था, जिसे मित्तल ने करीबी प्रतिद्वंद्वी बनना तो दूर की बात, कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं माना।

जियो भी कर रहा तैयारी

देश के दूरदराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रिलायंस जियो ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है 'जियो स्पेस फाइबर' है। जियो स्पेस फाइबर को पूरे देश में कम कीमत में उपलब्ध कराने की तैयारी है।

चीन में बढ़ रही रहस्यमय बीमारी, केंद्र के निर्देश पर अलर्ट मोड पर हैं राज्य

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन में इन दिनों सांस संबंधी रहस्यमय बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया चिंतित है। ष्ट लगातार नजर बनाए हुए है और चीन से ज्यादा डीटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच, भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 के संदर्भ में निगरानी रणनीति के लिए संशोधित गाइडलाइंस लागू करने के लिए कहा है। इसके तहत इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी की निगरानी बढ़ा दी जाती है। चीन में बच्चों में सांस संबंधी गंभीर बीमारी के कारण भारत में कम से कम 6 राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को अलर्ट मोड पर रखा है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत करने वाले मरीजों की देखभाल के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

कर्नाटक में अलर्ट

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों को मौसमी फ्लू के प्रति सचेत रहने को कहा है। मौसमी फ्लू के लक्षणों और जोखिम वाले कारकों को सूचीबद्ध किया गया है तथा सलाह में क्या करें और क्या न करें का भी जिक्र किया गया है। इसके तहत खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढंकना, बार-बार हाथ धोना, चेहरे को छूने से बचना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करना शामिल है।

राजस्थान ने बढ़ाई निगरानी

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन चिकित्सा कर्मचारियों को निगरानी रखनी चाहिए और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना चाहिए। यह भी कहा गया है कि बाल चिकित्सा इकाइयों और मेडिसिन विभाग में पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु को भी पूरी तैयारी की सलाह दी गई है।

केंद्र की गाइडलाइंस में क्या है

यह निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रविवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र के एक दिन बाद आया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों के उपायों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी गई है। जैसे- अस्पताल में बेड्स की उपलब्धता, इन्फ्लूएंजा के लिए दवाएं एवं टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट और रिएजेंट्स, ऑक्सीजन प्लांटों और वेंटिलेटर की कार्यक्षमता और स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाएं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को साल की शुरुआत में साझा किए गए 'कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए दिशानिर्देश' लागू करने की सलाह दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) की जिला और राज्य निगरानी इकाइयों द्वारा विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में आईएलआई/एसएआरआई के रुझानों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

आईएलआई या एसएआरआई का डेटा विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों से आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना जरूरी है। राज्यों को श्वसन रोगजनकों के परीक्षण के लिए एसएआरआई के रोगियों, विशेषकर बच्चों और किशोरों के नाक और गले के स्वाब के नमूने वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज (वीआरडीएल) में भेजने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा कि इन एहतियाती और सक्रिय उपायों के लागू होने से किसी भी संभावित स्थिति का मुकाबला करने और नागरिकों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित की जा सकती है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में चीन के उत्तरी हिस्से में सांस की बीमारी में वृद्धि का संकेत मिला है। यह मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एसएआरएस-सीओवी-2 आदि जैसे सामान्य कारणों के लिए जिम्मेदार है।

कहा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ-साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसी सांस संबंधी बीमारियों की प्रवृत्ति के साथ-साथ कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के कारण यह वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा, 'वैसे डब्ल्यूएचओ ने चीनी अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी मांगी है, लेकिन यह आकलन किया गया है कि फिलहाल किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है।'

रॉयल एनफील्ड ने अपने बहु-प्रतीक्षित एडवेंचर टूरर - ऑल न्यू हिमालयन का लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

रॉयल एनफील्ड ने ब्रांड के सबसे बड़े मोटरसाइकिल फेस्टिवल, मोटोवर्स 2023 में अपने एडवेंचर टूरर, ऑल न्यू हिमालयन का लॉन्च किया, जो क्षमता और उपयोगिता का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। यह हर सड़क पर और बिना सड़क के चलने के लिए बनाई गई है। इस महीने 5A 2023 में अनावरण के बाद ऑल न्यू हिमालयन भारत में रिटेल बिक्री और बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गई, और मार्च 2024 से पूरे यूरोप में मिलने लगेगी। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत यूके में £5,750 और पूरे यूरोप में 5900 होगी। भारत में हिमालयन 31 दिसंबर, 2023 तक INR 2,69,000 के विशेष प्रारंभिक मूल्य में मिलेगी। ऑल न्यू हिमालयन 3 अलग-अलग वैरिएंट- बेस, पास और समिट तथा हिमालय से प्रेरित 5 रंगों- काजा ब्राउन (बेस वैरिएंट), स्लेट सीरीज में पॉपी ब्लू और हिमालयन साल्ट (पास- मिड वैरिएंट), और हैनले ब्लैक एंड कामेट व्हाइट (समिट- टॉप वैरिएंट) में उपलब्ध होगी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका को भी जल्द ही एडवेंचर के लिए तैयार हिमालयन का अनुभव मिलेगा, जिससे पूरे विश्व के राइडर्स के लिए रॉयल एनफील्ड की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। इस मोटरसाइकिल के लॉन्च के बारे में रॉयल एनफील्ड के सीईओ, बी गोविंदराजन ने कहा, 'नई हिमालयन बनाने के लिए हमने पूरी दुनिया में घूमने वाले, खोज करने वाले और एथलीटों के साथ अपने राइडिंग समुदाय के अनुभव का उपयोग किया। उनके और हिमालय में हमारे अपने अनुभवों की मदद से हमने अपनी मोटरसाइकिल के डीएनए को बनाए रखते हुए पूरी तरह से हिमालय के लिए विकसित मोटरसाइकिल बनाई, जिसके हमें शानदार परिणाम मिले, जो पूरी दुनिया के ग्राहकों और विशेषज्ञों से हमें मिले प्यार से प्रदर्शित होता है। नई हिमालयन एक नई विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो वास्तविक राइडर्स की ज़रूरतों के अनुरूप है। यह पूरी तरह से एक ग्लोबल मोटरसाइकिल है, जो पूरी दुनिया में एडवेंचर टूरिंग श्रेणी में नए मानक स्थापित कर देगी। हमारी प्योर मोटरसाइक्लिंग की फिलॉसफी के अनुसार हम पूरे विश्व में अपने जोशीले समुदाय के लिए आगामी राइड कैलेंडर की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हैं।'

दुनिया की फैक्ट्री से घट रहा निर्यात

चीन के लिए नई मुसीबत बन रहा मिस्ट्री वायरस

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के सख्त नियम ने चीन की इकॉनमी को हिलाकर रख दिया। भले ही चीन अपने मुंह से कुछ न कहें, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ड्रैगन की पोल खोल रहे हैं। चीन में खत्म होती नौकरियां, बूढ़ी होती जनसंख्या, चीनी कंपनियों पर बढ़ता कर्ज का बोझ इकॉनमी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। चीन का रियल एस्टेट कारोबार , जो उसकी इकॉनमी का सबसे मजबूत खिलाड़ी है, वो ध्वस्त होता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का योगदान 30 फीसदी तक का है, लेकिन देश की बड़ी-बड़ी रियल स्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। चीन की इकॉनमी, वहां की जीडीपी, निर्यात-सप्लाई चेन सब हिला हुआ है। कोरोना महामारी की चोट से अभी चीन उबर भी नहीं नया पाया था कि नए मिस्ट्री वायरस ने चीन की मुश्किल को बढ़ा दिया है।

चीन में रहस्यमयी बीमारी

कोरोना के बाद एक फिर चीन में नई रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। जानकार चीन की इस नई तरह की बीमारी की भो कोविड-19 से जोड़ कर देख रहे हैं। चीन में यह बीमारी तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर फ़ैल रही है। अस्पतालों में बेड तेजी से भरते जा हुए हैं। नई बीमारी सिर्फ चीनी लोगों की सेहत नहीं बल्कि चीन की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले से आर्थिक रू से बीमार चीन को इस बीमारी ने जोर का झटका दिया है। ये बीमारी सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा रही है। चूंकि ग्लोबल इकॉनमी के दुनियाभर के देश एक दूसरे से बंधे हैं, इसलिए इसका असर भी व्यापक होता है।

चीन के निर्यात-सप्लाई चेन को झटका

चीन में फैल रही नई बीमारी ने एक बार फिर से ग्लोबल सप्लाई चेन के बाधित होने का डर पैदा कर दिया है। अगर बीमारी इसी तरह से फैलता रहा तो निर्यात प्रभावित होगा। बीमारी का प्रकोप बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होता, जिसका नुकसान चीन को होगा। चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का केंद्र है। अगर बीमारी बढ़ी, इसका प्रकोप बढ़ता रहा तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी। निर्यात गिरेगा। निर्यात गिरने का मतलब है चीन की इकॉनमी पर सीधा असर। चीन की अर्थव्यवस्था सप्लाई और निर्यात पर टिकी है, लेकिन इस बीमारी के कारण इस पर असर पड़ सकता है। चीन वैश्विक विकास का लगभग 40ड्ड हिस्सा है। चीन का आयात के मुकाबले निर्यात अधिक है। अगर बीमारी की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई तो जाहिर है कि चीन की इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा। कंपनियों का घाटा बढ़ता चला जाएगा। घाटे के दबाव में कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ सकता है। बैंकों का कर्ज फंसता चला जाएगा। जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा।

वायरस फैला तो अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका

जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। अगर चीन में मौजूद बीमारी की वजह से उस तरह की बाधा उत्पन्न हुई तो चीन की इकॉनमी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। चीन, भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। अप्रैल-अक्टूबर 2023 में चीन से भारत ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया है। अगर बीमारी फैली तो इस पर भी असर पड़ सकता है। कोरोना के बाद से ही चीन का निर्यात धीमा हो गया। चीन की इकॉनमी दबाव में है।

इंदौर के उद्योगपति श्री रोहित सभरवाल को 'उद्योग रत्न' सम्मान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर के जाने-माने उद्योगपति श्री रोहित सभरवाल जी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में 'उद्योग रत्न' सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय एम.एस.एम.ई मंत्री श्री नारायण राणे जी आमंत्रित रहे। बतादें कि श्री रोहित सभरवाल ट्रेनिंग उपकरणों के उत्पादन में महती भूमिका निभाते हैं। उद्यमिता विकास के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। रोहित सभरवाल ने अपने उद्योगिक क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है आपका प्रमुख क्षेत्र उद्यमिता और ट्रेनिंग उपकरण उत्पादन है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इंदौर के उद्योगपति श्री रोहित सभरवाल को 'उद्योग रत्न' सम्मान से सम्मानित करने का उद्देश्य उनके उत्कृष्ट योगदान को पहचानना और समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सार्वजनिक रूप से प्रेरित करना था। उन्होंने अपने व्यवसायिक क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियों के साथ-साथ समाज के लिए भी कई कदम उठाए हैं। श्री रोहित सभरवाल ने उद्योग क्षेत्र में अपनी अद्भुत योगदान के लिए उच्च स्तरीय प्रशंसा प्राप्त की है। उन्होंने योग्यता, समर्पण और प्रेरणा के साथ अपने क्षेत्र में अपना अद्भुत काम किया है और इस सम्मान की प्राप्ति के लिए वे पूरी तरह से पात्र हैं। श्री रोहित सभरवाल ने अपने क्षेत्र में योगदान के साथ-साथ समाज के भी लिए भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक सहायता के माध्यम से समाज के सदस्यों की मदद की है। इस सम्मान से सम्मानित होने के बाद, श्री रोहित सभरवाल को उनके क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करता है। समाज की सेवा में उनका सदैव योगदान सम्मानीय है और उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। श्री रोहित सभरवाल को 'उद्योग रत्न' सम्मान से सम्मानित करना उनके योगदान की सच्ची मान्यता है और वे इस सम्मान के पात्र हैं।

ग्रह-नक्षत्रों के दुष्प्रभाव से बचना है तो घर में जरूर रखें चांदी की ये चीजें

कई बार ग्रहों-नक्षत्रों के स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। नौकरी या व्यापार के साथ-साथ पारिवारिक जीवन और सेहत संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंडित आशीष शर्मा के मुताबिक, चंद्रमा मन को प्रभावित करते हैं। चंद्र दोष दूर करने पर जातक को जहां मानसिक शांति मिलती है, वहीं सेहत संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती है। पंडित शर्मा के मुताबिक, यदि आपको भी जीवन में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो घर में चांदी की कुछ चीजें जरूर रखना चाहिए।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

अलमारी में रखें चांदी का गिलास

हिंदू ज्योतिष के मुताबिक, एकादश भाव में स्थित राहु तथा पंचम भाव में विराजमान केतु की शांति के लिए चांदी के गिलास घर में जरूर रखना चाहिए। चांदी के ग्लास में पानी पीना भी शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती है। यदि आप इसका रोज उपयोग नहीं करना चाहते तो अलमारी में भी रख सकते हैं।

चांदी की डिब्बी

राहु दोष को दूर करने के लिए तिजोरी या अलमारी में चांदी की डिब्बी में पानी भरकर रखना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है तो डिब्बी में शहद भरकर जमीन में दबा देना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष दूर हो जाता है। आर्थिक दिक्कतें दूर होती है।

चांदी का हाथी

व्यापार में लाभ पाने के लिए घर में चांदी से बना हाथी रखना शुभ होता है। चांदी का छोटा हाथी पंचम और द्वादश में बैठे राहु को शांत करता है। व्यापार में लाभ मिलता है। आर्थिक बाधाएं दूर होती है। इसके अलावा शादी में देरी हो रही है तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह चांदी की एक गोली चांदी की ही चेन में पिरोकर पहनें। इससे जल्द विवाह होता है।

शनिवार को पीपल के पेड़ की इस तरह करें पूजा, खत्म होगी दरिद्रता!

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

अगर आपके काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम मे आपको सफलता नहीं मिल पाती है और आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं. जिससे दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जायेगी. शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से दरिद्रता दूर होती है. हिंदू परंपरा के अनुसार, पूजा-पाठ का बहुत महत्व है. शास्त्रों में कई पेड़-पौधों की पूजा का भी उल्लेख किया गया है. ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है. ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी-देवताओं का वास होता है. मान्यता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करने से घर की गरीबी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है.

ज्योतिषाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा कि जब मां लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था तो मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी जिसे दरिद्रता कहा जाता था. अलक्ष्मी ने अपनी बहन से अपने विवाह की बात कही तब भगवान विष्णु ने अपने शिष्य मौद्गल्य से विवाह करवा दिया जिसे कुछ लोग उद्दालक भी कहते हैं.जब ऋषि मौद्गल्य दरिद्रता को अपने आश्रम लेकर गए तो वहां प्रवेश करने से दरिद्रता ने मना कर दिया क्योंकि वहां साफ सफाई थी और दरिद्रता गंदगी व धन की कमी वाले स्थानों में रहना चाहती थी. बड़ी मुश्किल से ऋषि ने उसे मनाया. दरिद्रता अक्सर ऋषि को परेशान करती थी. एक दिन ऋषि दरिद्रता के साथ कहीं बाहर गए. दरिद्रता ने पीने के लिए पानी मांगा. ऋषि ने कहा मैं अभी लेकर आता हूं और आप इसी पेड़ के नीचे तब तक खड़ी रहना जब तक मैं न वापस आ जाऊँ. ऋषि के पास दरिद्रता से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका था. वह अपने आश्रम चले गए और वापस नहीं आए. वह शनिवार का दिन था और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता ऐसे ही रह गई. तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु का पूजन करता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है.

सूर्योदय से पहले पीपल को चढ़ाए जल

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,शनिवार को प्रातः काल पीपल को जल देने से बहुत लाभ मिलता है. शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाना चाहिए. उसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए. इससे मन को तो शांति मिलती ही है. साथ ही घर में भी सुख- शांति बनी रहती है और घर से क्लेश भी नहीं होती है. अगर आप रोजाना पीपल को जल चढ़ाते हैं तो ये और अच्छा है.

ऐसे करें पीपल की पूजा

शनिवार के दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय के पहले पीपल की पूजा करनी चाहिए. वहीं शनिदेव की विधिवत पूजा करें. इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं. इसके बाद पीपल के पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर, गंगाजल से इसे धोएं और ले आएं. अब पानी में थोड़ी हल्दी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें और दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर ह्रीं लिखें. इसके बाद पूजा स्थान पर इस पीपल के पत्ते की पूजा करें. पूजा के बाद पत्ते को अपने पर्स या तिजोरी में लगें. कुछ हफ्ते तक लगातार ऐसा काम करें. इससे घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी. मान्यताओं के अनुसार पीपल के पत्ते की पूजा करने से ईष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं.

शनि का नक्षत्र गोचर करेगा सुनहरे दिनों की शुरुआत

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय-समय राशि परिवर्तन करते हैं. इसी तरह ग्रह नक्षत्र भी बदलते हैं. ग्रहों के इन राशि और नक्षत्र गोचर का असर सभी राशि वालों के जीवन पर पड़ता है. कर्मफलदाता शनि भी नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं. साथ ही न्याय के देवता शनि और छाया ग्रह राहु में मित्रता होने से शनि का उनके नक्षत्र में रहना शुभ फल देता है. ऐसे में शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 3 राशि वालों के लिए विशेष शुभ माना जा रहा है. यही वजह है कि साल 2024 में भी इन राशि वाले लोगों को शनि का शतभिषा नक्षत्र में भ्रमण करना बेहद लाभ देगा. इन लोगों की धन-दौलत बढ़ेगी. उन्हें खूब तरक्की मिलेगी. कह सकते हैं कि इन लोगों के जीवन में सुनहरे दिनों की शुरुआत हो सकती है.

मेष राशिः मेष राशि के जातकों को शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश बहुत लाभ देगा. इन लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी. धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे. कारोबार में जमकर कमाई होगी. आपकी धन-संपत्ति बढ़ेगी. संतान प्राप्ति के योग हैं. निवेश से लाभ होगा, लिहाजा यह समय निवेश करने के लिए बहुत शुभ है. नया घर या गाड़ी खरीद सकते हैं.

वृष राशिः वृष राशि के लोगों को शतभिषा नक्षत्र के शनि शुभ फल देंगे. वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह, शनि के मित्र ग्रह हैं. लिहाजा शनि वैसे भी वृषभ राशि के जातकों पर मेहरबान रहते हैं. इन जातकों को धन लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आ सकता है. व्यापार में मुनाफा होगा. नौकरी में बड़ा पद मिल सकता है. परिवार में प्यार और खुशी का माहौल रहेगा. नई नौकरी प्रस्ताव मिल सकता है.

मकर राशिः मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हर मामले में शुभ नतीजे देगा. कामों में सफलता मिलेगी. आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे. कमाई के नए मौके मिलेंगे. जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. आपको समय-समय पर कहीं से धन लाभ होता रहेगा.

प्रीति योग में पांच दिसंबर को मनाया जाएगा भैरव जन्मोत्सव

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की काल भैरव अष्टमी पांच दिसंबर को प्रीति योग में आ रही है। इस दिन भगवान भैरव के जन्म की मान्यता है। कालभैरव मंदिर में मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शहर के अष्ट महाभैरव मंदिर में भी उत्सव मनाया जाएगा। छह दिसंबर को भगवान कालभैरव की सवारी निकाली जाएगी।

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

जन्मोत्सव मध्य रात्रि में प्रीति योग में

ज्योतिषाचार्य के अनुसार भैरव जन्मोत्सव गणना के अनुसार देखें तो इस बार भैरव जी का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में प्रीति योग में होगा। 27 योगों के अंतर्गत आने वाला यह योग विशेष लाभ देने वाला बताया गया है। इस दौरान की मध्य रात्रि साधना के अनुकूल फल प्रदान करती है। उज्जैन में अष्ट महाभैरव की यात्रा का विशेष है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिखंड में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उज्जैन के अष्ट महाभैरव में क्रमशः काल भैरव, विक्रांत भैरव, सीता सित भैरव, आताल पाताल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंड पाणि भैरव आदि का उल्लेख दिया गया है। उनकी विधिवत यात्रा एवं व्रत उपवास करने से इच्छित मनोरथ की प्राप्ति होती है।

घोड़े की नाल के इन उपायों को कर पाएं जीवन में तरक्की, शनिदेव की होगी कृपा

ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय है जिनको कर हम घर में हो रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। घर में सुख-समृद्धि को ला सकते हैं। ऐसा ही तरीका है घरों के मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा देना। आपने कई घरों के मुख्य दरवाजे पर इसको लगा भी देखा होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी ने विस्तार से बताया कि कैसे हम घोड़े की नाल के ज्योतिष उपाय कर जीवन में आ रही अशांति को दूर कर सकते हैं।

उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाएं घोड़े की नाल

घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से खुशहाली रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। घोड़े की नाल लगाते समय यह ध्यान में रखें कि उसको काले कपड़े में ही बांधे। उसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार पर लगा दें, जिससे घर में सभी स्वास्थ्य रहेंगे।

घोड़े की नाल का उपाय कर पाएं नौकरी में तरक्की

आपको करियर में आशा अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है तो घोड़े की नाल का उपाय कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन घोड़े की नाल से बने छल्ले को बीच अंगुली में पहन लें। ऐसा करते ही आपके खराब दिन चले जाएंगे और नौकरी में सफलता मिल सकती है।

घोड़ की नाल का उपाय कर पाएं रोगों से मुक्ति

आपके घर में कोई सदस्य को हर समय बीमार ही जकड़े रहती है। उसको कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं लेकिन आराम नहीं मिला है। ऐसे में घोड़े की नाल से बनी चार कील, सवा किलो उड़द की दाल और एक सूखा नारिलय लेकर आएं। फिर उसको बीमार आदमी के ऊपर से उतारकर बहती नदी में प्रवाहित करें। इस तरीके से रोग और ग्रह दोष से निजात मिल सकता है।

आईआईएम इंदौर और जर्मनी के एफएच मुंस्टर ने किया एमओयू

ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पेश करने बना रहे योजना

इंदौर। एजेंसी

वैश्विक सहयोग की श्रृंखला में विस्तार करते हुए आईआईएम इंदौर ने अब जर्मनी के एफएच मुंस्टर के साथ समझौता किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमाँशु राय, और एफएच मुंस्टर के प्रेसिडेंट, फ्रैंक डेलमैन और माइकल डर्कसन ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

प्रो. राय ने कहा कि यह हमारी सभी वैश्विक साझेदारियों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अकादमिक एक्सीलेंस, स्टूडेंट कनेक्ट और जॉइंट रिसर्च के अवसरों को गति देने पर केन्द्रित इस सहयोग से प्रसन्न हैं। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना और ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना जो सामाजिक रूप से जागरूक हों। यह सहयोग हमारे इसी उद्देश्य से मेल खाता है। शिक्षा में इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, एफएच मुंस्टर के साथ हमारे सहयोग में फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स की तैयारी शामिल है। यह समझौता ज्ञापन हमारे छात्रों को विविध दृष्टिकोण प्रदान करने, नवीन सोच-विचार अपनाने और विभिन्न संस्कृतियों के माहौल को समझने और स्वयं को आने वाले समय के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

एफएच मुंस्टर की प्रमुख शैक्षणिक टीम ने आईआईएम इंदौर के साथ सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। ल्योन, फ्रांस में आयोजित एक सम्मेलन में प्रो. राय के साथ बातचीत के दौरान, उनकी अकादमिक टीम आईआईएम इंदौर के व्यापक पाठ्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित हुई। उन्होंने आईआईएम इंदौर की पेशकशों और अपने छात्रों को समान समृद्ध अनुभवों के साथ सशक्त बनाने के उनके दृष्टिकोण के बीच एक आदर्श तालमेल पाया। इसी चर्चा ने समग्र शिक्षा और नवीन शिक्षण अनुभवों की साझा संस्कृति को अपनाने के लक्ष्य के साथ सहयोग की पहल को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि 1981 में स्थापित उनका शैक्षणिक प्रोग्राम भी इंटरनेशनल एक्सपोज़र पर जोर देता है। उन्होंने कहा, इसके अनुरूप, हम आईआईएम इंदौर के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं, जिसका लक्ष्य हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम और एफएच मुंस्टर में इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स में मास्टर प्रोग्राम और आईआईएम इंदौर के आईपीएम छात्रों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज करना है। इसके साथ ही, सहयोग का उद्देश्य जॉइंट रिसर्च, एजुकेशनल डाटा शेयरिंग, जॉइंट प्रोग्राम्स, और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स की पेशकश है।

पिछले पांच वर्षों में आईआईएम इंदौर ने अलग-अलग देशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से सहयोग किए हैं। इनमें बेल्जियम, इटली, नेपाल, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएई, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ताइवान, मिस्र और हांगकांग के संस्थान शामिल हैं। आईआईएम इंदौर का जर्मनी के एप्लाइड साइंसेज एचटीडब्ल्यूजी कॉन्स्टैन्ज़ विश्वविद्यालय के साथ सहयोग, एक जर्मन संस्थान (2020) के साथ पहली साझेदारी थी, और एफएच मुंस्टर, जर्मनी के साथ हालिया समझौता ज्ञापन जर्मनी के दूसरे संस्थान के साथ हुआ सहयोग है। ये सहयोग वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, और हमारा लक्ष्य अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच को और अधिक व्यापक बनाना और निकट भविष्य में अधिक प्रभावशाली सहयोग के साथ आना है।

एफएच मुंस्टर के बारे में: 1971 में स्थापित, एफएच मुंस्टर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ राज्य और निजी निर्माण और इंजीनियरिंग स्कूलों के एकीकरण से स्थापित हुआ। शुरुआत में लगभग 2,300 छात्र यहाँ पढ़ते थे, जिसका संख्या बढ़ते हुए 15,000 से अधिक हो गयी है। वे 100 से अधिक स्नातक और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में शामिल हैं। यहाँ एक इन-हाउस डॉक्टरेट कॉलेज है जिसमें 110 सहकारी डॉक्टरेट कैंडिडेट्स हैं। एफएच मुंस्टर एक अभ्यास-उन्मुख, अंतर्राष्ट्रीय और अंतःविषय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने की इसकी प्रतिबद्धता ने इसे जर्मनी के व्यावहारिक विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे सफल विश्वविद्यालयों में से एक बना दिया है।

बिना भारत लौटे US वर्किंग वीजा रिन्यू होगा, इंटरव्यू भी जरूरी नहीं

वॉशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका दिसंबर में H-1B वीजा की कुछ कैटिगरी के रिन्यूअल के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों को लाभ होगा। H-1B वीजा पर ही घ्ऊ कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों की संख्या में कर्मचारी भर्ती करती हैं। पायलट प्रोग्राम में केवल 20,000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा और इसकी घोषणा उस वक्त की गई थी जब जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी।

वीजा सेवाओं के लिए उप सहायक विदेश मंत्री जूली स्टफ्ट ने कहा, 'भारत में मांग (अमेरिकी वीजा) अब भी बहुत ज्यादा है। हम नहीं चाहते की इंतजार का समय छह, आठ और 12 महीने हो। हम यह तय करना चाहते हैं कि यात्रियों को जितना जल्दी हो सके इंटरव्यू का वक्त मिले। हम

एक ओर इसे घरेलू वीजा रिन्यूअल प्रोग्राम से कर रहे हैं जो काफी हद तक भारत पर केंद्रित है।' दिसंबर से तीन महीने की अवधि में विदेश मंत्रालय उन विदेशी नागरिकों को 20,000 वीजा जारी करेगा जो पहले से ही देश में हैं।

पिछले साल 1.4 लाख भारतीय छात्रों को US वीजा

अमेरिका ने पिछले साल 1 लाख 40 हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं। साथ ही अमेरिकी प्रशासन वीजा के वास्ते इंटरव्यू के लिए इंतजार का समय कम करने के लिए कई कदम उठा रहा है। वीजा सेवाओं के लिए उप सहायक विदेश मंत्री जूली स्टफ्ट ने कहा कि भारत में अमेरिकी मिशन ने यह सुनिश्चित करने के लिए हफ्ते में छह-सात दिन काम किया कि स्टूडेंट्स की क्लास शुरू होने से पहले उनका इंटरव्यू ले लिया जाए। स्टफ्ट ने कहा, 'हमने इस साल भारत में जो किया, उससे हम गौरवान्वित हैं। मेरा मानना है कि इतिहास में पहली बार हमने भारत में 10 लाख वीजा जारी करने का लक्ष्य रखा और न केवल हमने इसे पूरा किया, बल्कि यह काम कई महीने पहले ही कर लिया गया। इस तरह संख्या इससे कहीं आगे जाएगी।'

उन्होंने कहा, 'भारत से इस साल अमेरिका आने के लिए कामगारों, क्रू मेंबर्स के सदस्यों और छात्रों के आवेदन की रिकॉर्ड संख्या है। इंटरव्यू के लिए इंतजार का समय कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को भारत भेज रहे हैं।' ळए ने 2023 में अब तक एक करोड़ से ज्यादा वीजा जारी किए हैं जो कि उसके अनुमान से 20 लाख ज्यादा हैं। यह उसके विदेशी मिशनों के लिए अब तक की सर्वाधिक वीजा संख्या है।

पूर्व सैनिक कर्मियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए

स्किल इंडिया ने रिसेटलमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भारतीय सशस्त्र बल के साथ भागीदारी की

सेवानिवृत्ति के बाद 70,000 सशस्त्र बल कर्मियों का लाभकारी पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना

नई दिल्ली। स्किल इंडिया मिशन के प्रयासों को बढ़ावा देने और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेवा कर्मियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई), तेलंगाना ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (रक्षा मंत्रालय) के पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य एयरोस्पेस और एविएशन (ड्रोन टेक्नोलॉजी), कैपिटल गुड्स और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कम्प्रेहैन्सिव रिसेटलमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करना है।

साझेदारी के तहत, यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त होने वाले सेवा कर्मियों को नागरिक जीवन में, विशेष रूप से हाई-डिमांड वाले क्षेत्रों में पुनः शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम को विकलांग सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों सहित सशस्त्र सेवा कर्मियों के विविध स्किल सेट को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जो उनके सफल पुनर्वास के लिए 100ज्ञ रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है। भारत भर के सभी 33 एनएसटीआई में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद 70,000 सशस्त्र बलों के कर्मियों का लाभकारी पुनर्स्थापन सुनिश्चित किया जा सके।

फिनटेक यूनिट लाने की तैयारी में LIC, दिसंबर में ऑफर करेगी नई सर्विस

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एलआईसी (LIC) एक नई फिनटेक कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रही है। एलआईसी इसके लिए संभावनाएं तलाश रही है। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एलआईसी ने संपूर्ण डिजिटल बदलाव परियोजना (DIVE) शुरू की है। इस परियोजना को चलाने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद डीआईवीई प्रोजेक्ट के जरिए अपने सभी हितधारकों, ग्राहकों, मध्यस्थों, मार्केटिंग संबंधी लोगों और हर किसी के लिए अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इनिशिएटिव स्थापित करना है।'

उन्होंने कहा कि एलआईसी को ज्यादातर नए ग्राहक अपने एजेंट के जरिए मिलते हैं। इसके बाद अन्य सेक्टर्स में भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्लेम सेटलमेंट, लोन तथा अन्य सेवाएं एक बटन के 'क्लिक' पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

ग्राहकों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं

मोहंती ने कहा, 'ग्राहकों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए हमारी जरूरी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। हम वित्तीय प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और व्यवसाय के विस्तार में इसकी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे।' एलआईसी ने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चालू वर्ष में अब तक तीन फिनटेक कंपनियों को कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जोड़ा है। एलआईसी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में नई पॉलिसी के प्रीमियम में डबल डिजिट में वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से आने वाले महीनों में तीन से चार नए उत्पाद पेश करने की योजना बनाई है।

एलआईसी ला रही नई सर्विस

उन्होंने कहा कि एलआईसी दिसंबर के पहले सप्ताह में एक नई सर्विस ऑफर करने जा रही है। उम्मीद है मार्केट में इसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नई सर्विस की कुछ विशेषताएं साझा करते हुए मोहंती ने कहा कि यह सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करेगी और इसके पूर्ण होने के बाद पॉलिसीधारक को जीवन भर बीमा राशि का 10 फीसदी मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई सेवा बाजार में हलचल लाएगी क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि वह कितना भुगतान कर रहा है और 20-25 वर्षों के बाद उसे कितना रिटर्न मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऋण सुविधा और समय से पहले निकासी भी इस नई सेवा की विशेषताओं में शामिल है।

अमेज़न इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी ने

ई-कॉमर्स उद्योग के लिए इनोवेट और ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अमेजन इंडिया और पोर्ट्स, शिपिंग, एवं वाटर वेज मंत्रालय के अंतर्गत इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) ने एक श्दळ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत ग्राहकों के पैकेजों का परिवहन इनलैंड वाटरवेज द्वारा करना शुरू किया जाएगा। इस समझौते के बाद एमेज़ॉन इंडिया इनलैंड वाटरवेज का उपयोग करने वाली देश की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है, जिससे भारत में अपना परिवहन का ढांचा मजबूत करने का इसका उद्देश्य प्रदर्शित होता है। IWAI के साथ यह गठबंधन परिवहन के किफायती और सस्टेनेबल माध्यम के रूप में इनलैंड वॉटरवे का ज्यादा उपयोग करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप है।

इस समझौते के तहत एमेज़ॉन इंडिया और IWAI मिलकर कंटेनराईज़्ड कार्गो मूवमेंट संभव बनाएंगे और कार्गो शिपमेंट के लिए इनलैंड वॉटरवे के उपयोग का एक नेटवर्क स्थापित करेंगे। अमेज़न इंडिया अपनी सप्लाई चेन में इनलैंड वाटरवेज की संभावनाएं तलाशना शुरू करेगा, और ईंध एवं इसके कैरियर्स के सहयोग से जल्द ही पटना एवं कोलकाता वॉटरवेज़ पर पायलट रन शुरू किया जाएगा। इससे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाते रहने और ई-कॉमर्स में पारस्परिक लाभ की परियोजनाओं को तलाशने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय कैबिनेट मंत्री, पोर्ट्स, शिपिंग एवं वॉटरवेज़ मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा, ''एमेज़ॉन इंडिया के साथ यह समझौता ज्ञापन भारत के इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट की क्षमता का उपयोग करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा उद्देश्य नदियों द्वारा कार्गो मूवमेंट बढ़ाना है, जो परिवहन का ज्यादा किफायती और सस्टेनेबल

तरीका है। मैं वॉटरवेज परिवहन समाधानों का निर्माण करने के लिए IWAI के साथ सहयोग करने के लिए अमेजन इंडिया को बधाई देता हूँ। यह अभियान भारत में तेजी से विकसित होते ई-कॉमर्स सेक्टर में सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स समाधानों का महत्वपूर्ण उदाहरण है।''

इंदौर करेगा भारतीय फार्मा मेले के दसवें संस्करण की मेजबानी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फार्मास्युटिकल उद्योग, मार्केटिंग कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए ख़ास इंडियन फार्मा फेयर होने जा रहा है। इंडियन फार्मा मीडिया के द्वारा इंडियन फार्मा फेयर (आईएफएफ) 2024 के दसवें संस्करण का आयोजन 15 से 16 मार्च 2024 तक शेरेटन ग्रांड पैलेस में होगा। फार्मास्युटिकल उद्योग, मार्केटिंग कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्री के चिर परिचित लोगों की उपस्थिति में होगा , यह फार्मास्युटिकल उद्योग इंडस्ट्री कि सबसे बड़ी बी2बी प्रदर्शनी होगी। 'आईएफएफ एक प्रमुख व्यापार शो है जो फार्मास्युटिकल कंपनियों, फार्मा थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पीसीडी , फार्मा फ्रेंचाइजी को और वितरकों को नवीनतम, नवीन उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है। यह मेला फार्मा पेशेवरों और उद्योग भागीदारों के लिए है। इंडियन फार्मा फेयर बिजनेस के लिए एक फार्मा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस कार्यक्रम में जेनेरिक दवा निर्माताओं से लेकर आयुर्वेदिक और हर्बल दवा, सौंदर्य प्रसाधन, तकनीकी विकास इत्यादि पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इस फार्मा फेयर में देश भर से फार्मास्युटिकल उद्योग , मार्केटिंग कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज कंपनी के साथ ग्राहक, व्यवसायों और उनकी बिक्री जैसी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। आईएफएफ के महाप्रबंधक श्री बी एस भंडारी ने कहा' यह प्रदर्शनी भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग के विस्तार पर केंद्रित होगी, ज्यादातर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, पीसीडी/फ्रैंचाइज़ी के माध्यम से आयोजित यह कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर देश में दसवीं बार और इंदौर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इस फार्मास्युटिकल मेले में पूरे भारत से कारोबारियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न केवल आगंतुकों को उत्पादों उनके आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलेगी। आईएफएफ के नेतृत्व में इंदौर फार्मास्युटिकल उद्योगों की इस विकास गाथा में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 7000-8000 से अधिक कॉर्पोरेट शख्सियत के भाग लेने की उम्मीद है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एक नए प्लांट की स्थापना कर्नाटक में

बेंगलुरु। आईपीटी नेटवर्क

'मेक इन इंडिया' और 'सभी के लिए व्यापक खुशहाली' की अपनी प्रतिबद्धता के अनुकूल, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए ताकि नए निवेश के माध्यम से देश में कंपनी के मौजूदा परिचालन को बेहतर किया जा सके। भारत में टीकेएम के 25 वर्षों के परिचालन पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर के साथ, लगभग 3,300 करोड़ रुपये का यह निवेश एक नए संयंत्र की स्थापना के लिए है। इससे क्षमता में वृद्धि होगी और इस तरह स्थानीय विनिर्माण की पारिस्थितिकी तंत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत होगी और 'सबके लिए मोबिलिटी' तैयार की जायेगी। यह भारत में कंपनी का तीसरा प्लांट

होगा, जो कर्नाटक में बैंगलोर के पास बिदादी में स्थित है। यह विकास आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए आगे के निवेश और रोजगार सृजन की संभावना भी लाता है। कर्नाटक सरकार के साथ इस समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने हस्ताक्षर किए और इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। कंपनी की ओर से इसपर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मसाकाज़ु योशिमुरा ने दस्तखत किये। इस मौके पर श्री एमबी पाटिल, बड़े और मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री स्वप्नेश आर. मारू एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य अनुपालन अधिकारी, श्री विक्रम गुलाटी, कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट, श्री सुदीप संतराम दलवी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य संचार अधिकारी तथा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के अन्य शिखर के अधिकारी मौजूद थे।

एबॅट ने भारत में लॉन्च किया फ्रीस्टाइल लिब्रेलिंक मोबाइल ऐप

मधुमेह पीडितो के लिए मददगार

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हेल्थकेयर के क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख कंपनी एबॅट ने भारत में अपने डिजिटल हेल्थ टूल फ्रीस्टाइल लिब्रेलिंक ऐप को लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप फ्रीस्टाइल लिब्रे सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सुई चुभोए बगैर1 उनका ग्लूकोज लेवल मापने में मदद करेगा और इसकी रीडिंग उनके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड फीस्टाइल लिब्रे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर एबॅट डायबिटीज पर आसानी से निगरानी रखने, डेटा की जानकारी पाने और आसान कनेक्शन से लोगों को मजबूत करना चाहता है ताकि वे अपनी डायबिटीज का बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकें। यह मोबाइल ऐप आईफोन और एंड्रॉएड स्मार्टफोन पर काम करने के लिए उपलब्ध है।

फ्रीस्टाइल लिब्रेलिंक ऐप लोगों को उनके स्मार्टफोन पर रियल टाइम में उनके ग्लूकोज के स्तर को देखने और निगरानी करने की सुविधा देता है। वे ऐप की मदद से इस जानकारी को उनके डॉक्टर्स या केयरगिवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप यूजर्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज डेटा को सेंसर से मोबाइल ऐप में ट्रांसफर करता है, जिससे लोगों को भोजन, इंसुलिन का इस्तेमाल, दवा और व्यायाम का प्रबंधन करने के लिए आठ घंटे के ग्लूकोज का रिकॉर्ड रखने और रियल टाइम के पैटर्न की निगरानी करने में मदद मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से लोगों को अलग से ग्लूकोज निगरानी के लिए अलग से टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है।

ऐप के लॉन्च पर दक्षिण एशिया में एबॅट के डायबिटीज केयर बिजनेस के जनरल मैनेजर कल्याण सत्तारु ने कहा, 'मधुमेह से पीड़ित लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें इसका प्रबंधन करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होता है। फ्रीस्टाइल लिब्रेलिंक ऐप फ्रीस्टाइल लिब्रे सेंसर के साथ आसानी से जुड़ जाता है। यह सेंसर दुनिया का नंबर 1 कॉन्टीन्युअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग (सीजीएम) है, जिसका इस्तेमाल विश्व स्तर पर मधुमेह से पीड़ित 5 मिलियन2 से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। सीनियर डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. मनोज चावला ने कहा, 'वास्तविक समय में अपने आप ही ग्लूकोज की जानकारी मिलने से डायबिटीज रोगियों को उनकी देखभाल करने वालों के लिए आसान प्रबंधन की सुविधा मिलती है। नई डायबिटीज टेक्नोलॉजी सटीक और समझदारी से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करेगी।'

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।